(v) Financial difficulties of Kerala Government

SHRI V.S. VIJAYARAGHAVAN (Palghat): Under Rule 377, I make the following statement:

The State of Kerala is facing a serious financial crisis. There are two factors which are responsible for this crisis. Firstly, the Central Government amended the Central Sales Tax Act in 1976-77 and abolished the Sales Tax on commercial produce like pepper, tea, cashew, marine products etc. This has deprived the State of a revenue of about Rs. 183 crores. The resources position of the State is extremely tight.

The second reason is that the Central Government has strictly enforced the overdraft regulations. Kerala had run up an overdraft of Rs. 145 crores by June, 1982.

The Government of Kerala is trying its best to mobilise resources to meet its expenditure. But, there are major constraints on its capacity to mobilise resources to any large extent. Therefore, considering the seriousness of the matter, I request the Government to relax the conditions regarding overdraft and compensate in some way the loss suffered by Kerala on account of the abolition of Central Sales Tax on the commodities mentioned above.

(vi) Unsatisfactory Telephone Service of Firozabad

श्री राजेश कुमार सिंह : (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक एवं जनसंख्या के गहन घनत्व वाले शहरों में से एक है लेकिन अत्यन्त खेद की बात है कि यहाँ की दूर संचार व्यवस्था की हालत काफ़ी दयनीय है। दूर्भाष मिलने की सम्भावना नगण्य होने के कारण अनेक इच्छुक नागरिकों ने अपना पंजीकरण कराना तक बन्द कर दिया है। इनकी क्षमता बढ़ने के बजाय निरन्तर घटती जा रही है। गंदे तथा अंधेरे मार्ग पर वर्तमान दूरभाष केन्द्र का स्थान एवं भवन बहुत ही अनुपयुक्त हैं और इसमें कार्य-कुशलता का सर्वथा अभाव रहा है।

आगरा-फीरोज़ाबाद के निकट सम्पर्क के कारण 120 चैनल का सरकिट लगा दिया गया है, लेकिन स्वचालित संयंत्र की सुविधा के अभाव में इसका उपयोग सीमित ही नहीं है, अपितु दोनों शहरों के मध्य एस०टी०डी० की भी सुविधा नहीं उपलब्ध है। इसके लिये एक भूखण्ड क्रय किया गया था, ताकि वहां दूरसंचार केन्द्र का भवन निर्माण करा कर स्वचालित संयंत्र की व्यवस्था की जाय, लेकिन यह मामला विभिन्न कारणों से अधर में लटका हुआ है। फिरोज़ाबाद टेलीफोन एक्सचेन्ज का प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्र लखनऊ होने के कारण इस की व्यवस्था अपरिवर्तनीय है। वहां के लोगों ने कई बार सरकार से यह मांग की है कि इसे नवनिर्मित आगरा टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया जाय। इससे आगरा टेलीफोन परामर्शदात्री समिति पर फिरोज़ाबाद का भी प्रतिनिधित्व सम्भव होगा।

अत: इस सदन के माध्यम से संचार मंत्री जी से साग्रह अनुरोध है कि फिरोज़ाबाद दूरसंचार केन्द्र के भवन निर्माण हेतु अन्य स्थान की व्यवस्था तत्काल भवन निर्माण कराने, स्वचालित संयंत्र की स्थापना तथा फिरोज़ाबाद के इस टेलीफोन केन्द्र को आगरा टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में शामिल करने हेतु यथोचित कार्यवाही यथाशीघ्र करने की कृपा करें।

(vii) Need for staying the liquidation of Dandakaranya Development Authority

SHRI AJIT BAG (Serampore): Under Rule 377, I make the following statement:

It is a matter of great regret that despite the West Bengal State Government's request for staying the liquidation of Dandakaranya Development Authority, the Government of India has not changed its decision to wind up the DDA and that preparations have started on a large scale for transfer of assets and institutions of the DDA to the concerned State Governments in the name of 'normalisation of administration'.

A major task of the DDA, namely comprehensive and integrated development of the entire Dandakaranya area is still far